विचार बिन्दु

कुरूपता मनुष्य की सौंदर्य विद्या है। –चाणक्य

नई परीक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था बदलने की अपेक्षा

भारत की शिक्षा प्रणाली लंबे समय से परीक्षा-केंद्रित रही है। विद्यार्थियों की प्रतिभा और क्षमता का मूल्यांकन मुख्यत: लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही किया जाता रहा है। इस परंपरागत पद्धति में वर्षों से यह धारणा बनी रही है कि अंक ही विद्यार्थी की बुद्धिमत्ता और भविष्य का निर्धारण करते हैं। किंतु बदलते समय, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में शिक्षा के उद्देश्यों का दायरा अब केवल अंक हासिल करने तक सीमित नहीं रह गया है। संभवत: इसी सोच को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक नई परीक्षा नीति लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। सीबीएसई की नई परीक्षा नीति के मूल में यह भावना है कि विद्यार्थियों को रटने वाली शिक्षा से मुक्त किया जाय। उसकी जगह उन्हें समझने, सोचने और लागू करने वाली शिक्षा की ओर ले जाया जाय। इस नीति का केंद्र बिंदु यह है कि विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनें, न कि केवल परीक्षा के समय अपना रटा हुआ ज्ञान दोहराने वाले बने रहें। नई नीति के अनुसार वार्षिक परीक्षा प्रणाली की जगह अब मल्टी-लेवल मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाना है। कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं द्वि-टर्म प्रणाली में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के प्रश्न पत्रों में क्षमता आधारित प्रश्नों का अनुपात बढ़ाया गया है, ताकि विद्यार्थी का मूल्यांकन केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि उसके तर्क, विश्लेषण और समस्या-समाधान कौशल के आधार पर हो सके। इसमें आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग को अधिक महत्व दिया गया है। इसके अलावा ओपन बुक एग्जामिनेशन, असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन और डिजिटल आकलन प्रणाली जैसी विधियों को भी धीरे-धीरे इसमें जोड़ा जाने की व्यवस्था की गई है। रटंत की संस्कृति से मुक्त होने की पहल इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए तथ्यों को रटने पर जोर देते हैं, बजाय उनके अर्थ को समझने के। इसका कारण शायद भारतीय पुरातन शिक्षा प्रणाली रही है जिसमें सारा ज्ञान मौखिक था। संस्कृत के मंत्रों में समाहित ज्ञान को गुरु अपने शिष्यों को रटा कर ही देता था। नई नीति इस प्रवृत्ति को बदल सकती है। जब प्रश्न 'क्यों', 'कैसे' और 'क्या होगा यदि' जैसे होंगे, तो विद्यार्थी को सोचने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इससे शिक्षा किताबों से बाहर आकर जीवन कौशल का रूप ले सकेगी। उदाहरण के लिए, पहले यदि विज्ञान में 'जल चक्र' पर प्रश्न आता था तो विद्यार्थी परिभाषा याद कर लेते थे। अब प्रश्न यह होगा कि – यदि जल चक्र रुक जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? – ऐसा प्रश्न विद्यार्थियों को सोचने पर मजबूर करेगा।

नई नीति से शिक्षकों की भूमिका में भी बदलाव आने की अपेक्षा है। कह सकते हैं कि नई परीक्षा नीति केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा परिवर्तन की आशा लेकर आई है। नई नीति केवल 'पाठ पढ़ाने' की सीमित भूमिका से शिक्षकों को निकाल कर उन्हें सही अर्थों में विद्यार्थियों के मार्गदर्शक और मूल्यांकनकर्ता बनने की अपेक्षा करती है। शिक्षकों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थी केवल सिलेबस न पढ़ें, बल्कि विषय को समझें और उसे अपने वास्तविक जीवन में लागू कर सकने योग्य बनें। शिक्षकों को उनकी नई भूमिका के लिए तैयार करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रमों को भी अद्यतन करके मजबूत बना रहा है, ताकि शिक्षकों को नई मूल्यांकन प्रणाली के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके। ऐसा माना गया है कि नई नीति से विद्यार्थियों पर अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। मसलन उन पर अंक लाने का दबाव घटेगा। पहले एक ही परीक्षा में सब कुछ दांव पर होता था, अब टर्म-वाइज और लगातार मूल्यांकन से विद्यार्थियों पर दबाव कम होने की आशा की जा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जब विद्यार्थी को परियोजनाओं, प्रस्तुतिकरण और व्यवहारिक ज्ञान पर अंक मिलेंगे, तो उसे अपने काम में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच का विकास भी होगा क्योंकि अब विद्यार्थियों को एक बंधे-बंधाये ढांचे के बाहर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई व्यवस्था में डिजिटल साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई प्रणाली में डिजिटल उपकरणों और तकनीकी मूल्यांकन की भूमिका बढ़ेगी, जिससे विद्यार्थी तकनीकी रूप से सशक्त होंगे। नई व्यवस्था शिक्षा में समानता की ओर एक कदम मानी जा सकती है। इस नई परीक्षा नीति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह समान अवसर प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अतीत में ग्रामीण या कमजोर वर्ग के विद्यार्थी अक्सर परीक्षा पद्धति के कारण पिछड़ जाते थे। नई नीति में प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट और स्कूल आधारित मूल्यांकन को महत्व देने से हर विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलेगा। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, यह पहल विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास पर जोर देती है – यानी कला, खेल, तकनीक और नैतिकता जैसे क्षेत्रों को भी इसमें शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। नई परीक्षा नीति और रोजगार कौशल की बात पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि आज का युग केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल पर आधारित है। नई परीक्षा नीति विद्यार्थियों में अनेक क्षमताएं विकसित करने में सहायक होगी। जैसे, समस्या समाधान, संचार कौशल, टीमवर्क और नेतृत्व, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच। आशा की जा सकती है कि जब विद्यार्थी इन क्षमताओं के साथ विद्यालय से निकलेंगे, तो वे न केवल उच्च शिक्षा में बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी अधिक सक्षम साबित होंगे।

बोर्ड की नई परीक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। यह केवल मूल्यांकन का तरीका नहीं बदलती, बल्कि पूरी शिक्षा की सोच को बदल देती है। यह विद्यार्थियों को केवल 'नौकरी पाने वाला' नहीं, बल्कि सोचने वाला, सृजनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज, सभी की सक्रिय भूमिका जरूरी है।

लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। नई व्यवस्था लागू करने में अनेक चुनौतियां सामने आएंगी। मगर यह भी सच है कि किसी भी नई नीति के साथ चुनौतियां भी आती ही हैं, और इस नीति के साथ भी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां नज़र आती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी सबसे बड़ी चुनौती होगी। डिजिटल मूल्यांकन या प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा के लिए आवश्यक साधन हर स्कूल में उपलब्ध नहीं हैं। यहां राज्य सरकार से अपेक्षा होगी कि वह प्रत्येक स्कूल में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करने में कोई कंजूसी नहीं बरते। बजट के किसी और मद में कमी करके भी इस पर खर्च करने के लिये सरकार को प्रवृत्त होना होगा। इसके साथ ही बड़ी चुनौती होगी शिक्षकों के प्रशिक्षण की। हमारा अनुभव बताता है कि शिक्षक प्रशिक्षण का काम पिछले दौर में लगातार कम होता चला गया है। शिक्षक नई मूल्यांकन प्रणाली को पूरी तरह समझ सकें इसके लिये उनके सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था तुरंत करनी होगी। शिक्षक को ही यदि नयी व्यवस्था की समझ नहीं होगी तब भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, जो सारे नवाचार का सत्यानाश करके रख सकती है। आज के हालात में सबसे बड़ी चिंता मूल्यांकन में निष्पक्षता को लेकर है। जब आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व मिलेगा, तो कुछ स्थानों पर पक्षपात की आशंका भी बढ़ सकती है। जिस प्रकार का हमारा समाज और राज की व्यवस्था है, जिसमें हर स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नजर आता है, वहां आंतरिक मूल्यांकन की निष्पक्षता का सवाल उठना स्वाभाविक है। हमें अभिभावकों की सोच को भी बदलना होगा। अभी अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों द्वारा केवल 'अच्छे अंक' पा लेने को सफलता का पैमाना मानते हैं। अभिभावकों को ऐसी मानसिकता से बाहर लाने के लिये प्रयत्न करने होंगे। यह काम कौन करेगा, यह एक लाख टके सवाल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दीर्घकालिक योजना बनानी होगी, जिसमें स्कूलों का डिजिटल सशक्तीकरण, टीचर ट्रेनिंग, और अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम शामिल हों। इसे केवल कागजों तक सीमित नहीं करने के बजाय योजना को कड़ाई से और व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करना होगा। यह भविष्य की दिशा है। यह दिशा है विद्यार्थी को शिक्षण से सीखने की ओर ले जाने की। नई परीक्षा नीति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शिक्षा का केंद्र अब अध्यापक नहीं, बल्कि विद्यार्थी होगा। उसे केंद्र में रख कर सबको अपना काम करना है, क्योंकि अब यह प्रणाली 'टीचिंग' से अधिक 'लर्निंग' पर केंद्रित होगी। यह तभी हो सकता है जब विद्यार्थी शिक्षा में निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिभागी बनें। परीक्षा के भय को भी समाप्त करना है जो अधिकतर सीखने में बाधा बनती है। इस बाधा को अवसर में कैसे बदलें यह बड़ी चुनौती सभी के सामने होगी। बोर्ड की नई परीक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। यह केवल मूल्यांकन का तरीका नहीं बदलती, बल्कि पूरी शिक्षा की सोच को बदल देती है। यह विद्यार्थियों को केवल 'नौकरी पाने वाला' नहीं, बल्कि सोचने वाला, सृजनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज, सभी की सक्रिय भूमिका जरूरी है। यदि यह नीति अपने उद्देश्य के अनुरूप लागू की जाती है, तो आने वाले वर्षों में भारत की शिक्षा प्रणाली अधिक न्यायसंगत, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी बन जाएगी। इसलिए सीबीएसई की नई परीक्षा नीति केवल 'परीक्षा' की व्यवस्था नहीं, बल्कि शिक्षा की परिभाषा बदलने की पहल है – एक ऐसी पहल जो आने वाली पीढ़ियों को न केवल अधिक ज्ञानवान, बल्कि अधिक विवेकशील और मानवीय बना सकती है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है दुनिया



कुमार अजय

■ डायरी

पंचकूला की घटना सन्न कर देने वाली है। आठ साल के बच्चे का छह साल की बच्ची को राक्षसी बर्बरता से मरणासन्न होने तक पीटना रूह कंपा देने वाला है। उस पर सिस्टम की संवेदनशीलता यह कि घटना के घंटों बाद लड़की को उसके परिजनों द्वारा ही संभाला जाता है। यूं तो इन दिनों हिंसा और अपराध की जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, इस माहौल अब किसी भी बात पर हैरत नहीं होती। कोई भी चीज अप्रत्याशित नहीं लगती। जैसे सबसे ज्यादा नवाचार अपराध के क्षेत्र में ही हो रहा है। हर बार कोई नया विचार, नया कारण, नया तरीका और नया अपराध। फिर भी पंचकूला ही घटना दिल दहला देने वाली है। अमेरिका जैसे विकसित देशों से बच्चों की हिंसक प्रवृत्ति की खबरें आती रहती हैं लेकिन हमारे यहां यह पैटर्न अभी नहीं है। इस घटना को भी स्कूल के शिक्षकों की लापरवाही और वहां निगरानी की कमी कहकर टाला जा सकता है।

सरकार भी कुछ शिक्षकों पर कार्यवाही कर अपने जिम्मेदार होने का अहसास दे सकती है। व्यवस्था पर सवाल जायज भी है। स्कूल अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। क्या सब कुछ चौकीदार और सीसीटीवी के भरोसे छोड़ दिया जाना उचित है। हमारे बच्चे किस दिशा में जाएं, इस बारे में स्कूल, शिक्षकों और शिक्षा विभाग को सोचना ही चाहिए। फिर भी, इसे केवल स्कूल और व्यवस्था का मामला बताकर इतिश्री कर लिया जाना अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना ही है। खबरों के मुताबिक, आठ साल के लड़के द्वारा छह साल को पागल कहा गया। बच्ची ने इसकी शिकायत करने की बात कही तो लड़के की यह हिंसक प्रतिक्रिया थी। लड़के को फांसी दिए जाने तक की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। कितना अजीब है कि हम पिटाई करने वाले बच्चे को केवल एक अपराधी के तौर पर देख पा रहे हैं। जाने हम कब समझ पाएंगे कि बच्चा स्वयं भी पीड़ित ही है, जो शायद ही आपकी आंखों में बसी नफरत को जान पा रहा हो। यहां अपराधी है तो संवेदनाशून्य समय और भ्रमित हम सब, जिनके पास बच्चों के नाम हमसे पूरे न हो पाए सपने, हमारी शेष रही महत्वाकांक्षाएं और कुछ हासिल न कर पाने की कुंठाएं महज हैं।

इसी बरस जून में ग्यारह-बारह साल के दो-तीन बच्चों द्वारा जयपुर में एक दस वर्षीय बालक की हत्या की घटना भी चर्चा में रही। वजह महज यह सामने आई कि बालक ने आरोपितों में से एक बच्चे की बहन के बारे में कुछ कह दिया था। आरोपित बच्चों ने इतने योजनाबद्ध ढंग से कत्ल को अंजाम दिया कि मृतक की लाश तक घटना के कितने ही दिनों बाद बरामद हुई। उन्हीं दिनों, सूबे की एक जेल में 100 से ज्यादा आपराधिक प्रकरणों वाले एक बंदी की दूसरे बंदी द्वारा हत्या भी चर्चा में रही। संयोग से उसमें भी बहन के बारे में अपशब्द कहे जाने का प्रकरण सामने आया था।

अजीब है कि एक पेशेवर अपराधी जिस कारण से किसी की हत्या करता है, उसी कारण से दस-बारह साल का लड़का भी किसी बालक की हत्या कर सकता है। अपराध की दुनिया से जुड़े व्यक्ति का किसी को कत्ल कर देना हैरान नहीं करता लेकिन इतनी ग्यारह-बारह साल के लड़के मिलकर इस तरह किसी का कत्ल कर सकते हैं या आठ साल का लड़का इतना हिंसक हो सकता है, यह सोचकर ही अजीब लगता है। इन बच्चों के हाथ से हो रहे अपराध हमें यह बताते हैं कि कथित तौर सभ्य होते जा रहे हम वास्तव में एक रुग्ण होते समाज हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा, हत्या या दूसरे अपराध नए नहीं लेकिन मासूमों की यह भागीदारी दुखद आश्चर्य पैदा करती है।

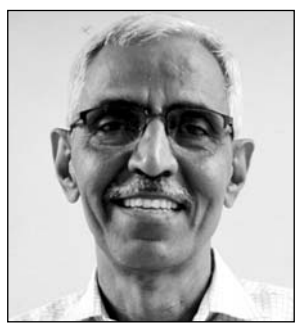
इन घटनाओं से भी बड़ी त्रासदी है कि हम किसी भी घटना के बाद या तो केवल सरकार और व्यवस्था को कोसने में जुट जाते हैं या फिर धर्म-जाति का सनसनी पैदा करने वाला कोई एंगल ढूंढकर चीरफाड़ में जुट जाते हैं जबकि इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों से मुंह फेर लेते हैं। क्या हम कभी सोच पाएंगे उन कारणों पर जिनके चलते हमारे बच्चे इस तरह हिंसक होते जा रहे हैं। व्यवस्था में बहुत कुछ ऐसा है, जहां आम आदमी के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं लेकिन एक परिवार, समाज और अभिभावक के तौर पर भी यदि कोई समुचित भूमिका हम निभा पाएं तो यह कम पर्याप्त नहीं है। विडंबना है कि आज संयुक्त परिवार में हमारा विश्वास रहा नहीं, बच्चों के लिए हमारे पास समय है नहीं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आसमान छूती इमारतों वाले महंगे स्कूल, अच्छे कपड़े और दूसरी सुविधाएं ही अच्छी परवरिश नहीं है। हमने इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया है कि बच्चे हमारी बात ध्यान से सुन पा रहे हैं या नहीं। क्या हम अपने बच्चों की बात ध्यान से सुन रहे हैं। रोजमर्रा की अच्छी-बुरी घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है। बच्चों की गलतियों पर हम किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। क्या हमें मालूम है कि हमारा बच्चा किस तरह की मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। क्या हमने बच्चों को बताया कि हार या असफलता का मतलब अपमान नहीं है। क्या हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपमान, असमहमति और असफलता का सामना किस प्रकार किया जाना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को संवेदनशील इंसान बना रहे। क्या हमने कभी स्वावलंबी होने का मतलब उन्हें सिखाया। दूसरे संप्रदायों, जातियों और लोगों के लिए हमारी सोच क्या बच्चों को भी जहरीला और हिंसक नहीं बना रही। यह जहर हम रखते तो दूसरों के लिए हैं, लेकिन सर्वाधिक दुष्प्रभाव हम खुद ही झेलते हैं। आत्मरक्षा के नाम पर रखे जाने वाले हथियार अकसर आत्महत्या में काम आते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि बच्चों को हर समय कोसते रहने या उपदेश देते रहने से वे नहीं सीखते हैं। वे हमारे आचरण से सीखते हैं और यह प्रक्रिया इतनी सहज और स्वाभाविक होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने अपने बच्चों में क्या इंजेक्ट कर दिया।

यह देखना अजीब है कि नवजात से लेकर किशोरों तक को चुप कराने, बहलाने और नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका हमारे पास मोबाइल ही रह गया है। बच्चों के हर सवाल का जवाब हमारे पास एआई या नई शब्दावली में कहें तो एसआई (सुपर इंटेलीजेंस) है। दुखद है कि बडी तनख्वाह लेने वाले शिक्षक मोबाइल के सहारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे जमाने में उन शिक्षकों को बेहतरीन माना जाता था जो बिना किताब हाथ में लिए पूरा कालांश पढ़ा देते थे। किसी मुश्किल सवाल के लिए हम कुंजी का उपयोग कर तो लेते थे लेकिन उस 'अवांछित' की खरीद के लिए पिताजी को राजी करना ही बड़ा मुश्किल था और फिर बस्ते में किसी तस्करी के सामान की तरह उसे शिक्षकों से छिपाकर और रखना पड़ता था। आज बच्चे सारे होमवर्क और पढ़ाई के लिए मोबाइल, इंटरनेट और एसआई पर निर्भर हो गए हैं। इसमें भी कुछ अच्छा होता ही होगा लेकिन बच्चे की सीखने की प्रक्रिया तो कुंद हो ही जाती है। कॉलेज की बच्चों को भी सब्जी और दूध का हिसाब जोड़ने में कागज-पेन या केलकुलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है जबकि एक-दो पीढ़ी पहले के अनपढ़ लोग अंगुलियों पर या जुबानी ही यह हिसाब जोड़ लिया करते थे। पाठ्यपुस्तकों को ध्यान से पढ़कर उत्तर तलाशने या उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया में बच्चे के भीतर जो विषयवस्तु गहरे तक चली जाती थी, अब वैसी उम्मीद ही करना व्यर्थ है। हमारे बच्चे आसान की ओर बढ़ रहे हैं और सब कुछ उन्हें मोबाइल पर उपलब्ध है। शिक्षण मनोविज्ञान एकदम पीछे छूट गया है। बाल मनोविज्ञान की हमें परवाह नहीं है। हम सब किसी न किसी मनोरोग के शिकार लोग हैं और वातावरण कहें या आनुवांशिकता, बच्चों को भी यही उपहार दे रहे हैं। पढ़ाई के बहाने बच्चों के जीवन में मोबाइल के सहारे हिंसा उतरी जा रही है, हमें न इसकी परवाह है और न ही इतना सोचने की फुरसत। उन्हें जिंदगी बस एक वीडियो गेम या वेब-सीरिज नजर आने लगी हैं, जहां बस गुस्सा है, गालियां हैं और हिंसा है। 'अहिष्णुता' के राजनैतिक मायने कुछ भी हों, हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे, आपके, सबके जीवन में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है और इसका सर्वाधिक असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है।

बहरहाल, बच्चों की हिंसक प्रवृत्तियों से जुड़ी ये घटनाएं महज एक शुरुआत है और दुआ ही की जा सकती है कि हम बाल-समाज में आ रहे इस बदलाव के इन संकेतों को समझेंगे और अपने-अपने स्तर पर इसे रोकने की जहमत उठाएंगे। यदि फिर भी हमें लगता है कि ये महज खबरें हैं, जिनमें 'कोई' लड़का है और 'किसी की' बच्ची है तो फिर इनमें अगला नंबर आपके या मेरे बच्चे का भी हो ही सकता है। ये बच्चे भी आपके और हमारे ही हैं। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक सरल, सहज और सुखी जिंदगी की ओर हमें अपने खुद को और अपने बच्चों को लेकर जाना है, जिसमें हम जान और सीख जाएं कि जिंदगी में असहमति, अपमान और असफलता पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। और हमारी हो न हो, बच्चों की दुनिया तो उतनी ही मासूम और खूबसूरत हो, जिसमें निदा फाजली साहब को अपनी बात वापस न लेनी पड़े। फाजली साहब फरमाते हैं– ''जितनी बुरी कही जाती है/उतनी बुरी नहीं है दुनिया/बच्चों के स्कूल में शायद/तुमसे मिली नहीं है दुनिया''। बच्चों की दुनिया वैसी ही खूबसूरत बनी रहे, आओ दुआ करें और अपने हिस्से की कोशिश करें।

कुमार अजय, साहित्यकार

तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा!



रामनिवास मेहता

अगले वर्ष हम हमारे राष्ट्र का 81वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम दुनिया के भ्रष्टतम राष्ट्रों में सम्मिलित है। एक सौ बिन्दुओं के पारदर्शी पैमाने पर हमारे अंक मात्र 39 हैं जो चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश से भी कम हैं और सिंगापुर के 84 अंकों से तो आधे भी नहीं है।

सिंगापुर भी आज के 40 वर्षों पूर्व तक भ्रष्टाचार में भारत की वर्तमान स्थिति जैसा ही था । वर्ष 1986 में सिंगापुर के राष्ट्रीय विकास मंत्री तह चियांग ने दो बार रिश्वत में 10 लाख से अधिक डॉलर प्राप्त किए और इसकी जानकारी वहां के प्रधानमंत्री ली क्वान यू को हुई। इस पर वहां की सीपीआईबी यानी करप्ट प्रैक्टिसेज इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से इसकी जांच करवाई गई। रिश्वत की यह राशि भूमि विकास प्रोजेक्ट के अनुमोदन एवं निजी विकासकर्ताओं को भूमि दिए जाने से संबंधित प्रोजेक्ट्स में ली गई थी। इस रिश्वत कांड की जांच के दौरान जब सीपीआईबी ने मंत्री के भ्रष्टाचार के प्राथमिक साक्ष्य प्रधानमंत्री ली को दिए तो प्रधानमंत्री ने इस कांड की सार्वजनिक रूप से पूर्ण जांच कराने की अनुमति प्रदान की, जिसकी भारत में कल्पना ही की जा सकती है।

राष्ट्रीय विकास मंत्री तेह चियांग ने प्रधानमंत्री से मिलकर मामले को गुपचुप तरीके से सुलटाने का प्रयास किया तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इस बारे में बताते हुए विकास मंत्री से तब तक नहीं मिलने की घोषणा कर दी जब तक कि सीपीआईबी द्वारा पूरा अनुसंधान एवं जांच नहीं हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी राजनेता और मित्र कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षित यानी इम्यूनिटी प्राप्त नहीं कर सकता है। सीपीआईबी की तफ़्तीश पूरी होने के पश्चात जब रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने वाली ही थी उसी दिन 14 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री ली को सीधे ही निम्न लेख करते हुए आत्महत्या कर ली: ;प्रधानमंत्री जी, मैं पिछले दो हफ़्तों से बहुत दुखी और निराश महसूस कर रहा हूँ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं खुद को ज़िम्मेदार मानता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इसकी पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। एक सम्मानित ओरिएंटल जेंटलमैन होने के नाते, मुझे लगता है कि यही उचित होगा कि मैं अपनी गलती की सबसे बड़ी सजा भुगतूँ!; इसके 1 महीने बाद 26 जनवरी 1987 को जब भारत अपना 38 वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन सिंगापुर के प्रधानमंत्री वहां की संसद में उनके राष्ट्रीय विकास मंत्री के उक्त सुसाइड नोट को पढ़ रहे थे और सीपीआईबी ने अपनी जांच में क्या पाया यह भी राष्ट्र को बता रहे थे। बस उसके बाद क्या था। सिंगापुर दुनिया के भ्रष्टतम देश से निकल कर दुनिया के नगण्य भ्रष्ट देशों में सम्मिलित हो गया क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार के संबंध में प्रधानमंत्री ने किसी भी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया था।

अब भारत के कई आईएएस और अन्य अधिकारी प्रतिवर्ष सिंगापुर के विकास, व्यवस्थाओं का और वहां भ्रष्टाचार नगण्य कैसे है इसका अध्ययन करने के लिए सरकारी व्यय पर यात्रा करके वहां कई तरह के कोर्स करके भारत लौटते हैं। भारत लौटकर वह भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कितनी कमर कस लेते हैं, यह भी अब हम सब जानते हैं।

आईए अब हम हमारे गृह राज्य राजस्थान की बात करें।राजस्थान में अभी हाल ही में एक समाचार आया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव रहे एक आईएएस अधिकारी एवं उनकी आईपीएस पत्नी ने गत दो वर्षों में इस प्रकार से संपत्ति बनाई जिस प्रकार से कोई जादूगर हमें जादू दिखाता है। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो उनमें से कई ने यह प्रश्न पूछा कि क्या राज्य के मुखियाजी को इस अधिकारी की कार्य प्रणाली पर क्या कभी किसी प्रकार की आशंका नहीं हुई और वह भी तब जब वह उनके ही सचिव बने हुए थे। प्रश्न अनेक हैं और उनमें से कई गंभीर भी हैं।

अब वह समय आ गया है जब नागरिकों को निडर होकर नेताओं और अफ़सरों पर चौकन्ने चौकीदार की नजर रखते हुए बारीकी से निगरानी रखनी चाहिए। राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ से ज्यादा है। राज्य में 200 एमएलए हैं, 292आईएएस और 212आईपीएस हैं। जनता के इन तीनों वरिष्ठतम पब्लिक सर्वेंट आकाओं को जोड़े तो इनकी संख्या 800 भी नहीं होती है। यह 800 लोग यदि वास्तव में सच्चे और ईमानदार हो जाए तो कुछ ही वर्षों में पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकती है परंतु इनमें से अनेक का वास्तविक चरित्र और दिखावटी चरित्र में दिन रात का अंतर है, एवं इनमें से कई बहरूपिया बने हुए हैं।।

यदि इन सब 800 लोगों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीयों पर बारीकी से निगरानी रखने का तंत्र विकसित कर दिया जावे तो निश्चित ही हालात में बड़े सुधार हो सकते हैं परंतु इसके लिए बहुत बड़े दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा की पवित्रता सबसे पहले ऊपर जरूरी है। उसको देखकर के ही नीचे के लोग भ्रष्ट होने या नहीं होने का मानस बनाते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जावे तो किसी भी मंत्री, एमएलए, अखिल भारतीय सेवाओं या राज्य सेवाओं के अन्य किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो कि वह भ्रष्टाचार करने की सोच भी सके और बहरूपिया का जीवन जीते हुए समाज सेवा, राष्ट्र सेवा या सरकारी सेवा करने का ढोंग कर आम आदमी द्वारा दिए जाने वाले टैक्स को घुन की तरह चट करते रहें।

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जैसे शरीर जर्जर होता है, बूढ़ा होता है, वैसे ही भारतीय गवर्नेंस सिस्टम भी अब कई तरह की बीमारियों से युक्त हो होकर लगभग कैंसर ग्रस्त हो गया है, इसको लगातार कई कीमोथेरेपी की आवश्यकता हो गई है। यदि राजस्थान के एक बार से अधिक समय के लिए एमएलए, जिला प्रमुख, प्रधान, एवं सरपंच रहे व्यक्ति, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीयों सहित अभियन्ता वर्ग के अधिकारीयों की संपत्तियों की किसी स्वतंत्र थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाई जावे और राजनेताओं के साथ उनके नेक्सस की जांच की जाए तो राजस्थान के नागरिकों को ज्ञात होगा कि हम किस रसातल की ओर जा रहे हैं।

सरकारी नौकर की 5 -10 साल की सेवा के पश्चात ही पता लग जाता है कि उसके घर में सरकारी धन की क्या रंगत आ रही है। इसी प्रकार की जानकारी एक पुराने पार्षद, सरपंच, प्रधान या अन्य नेता के सम्बन्ध में जनता को होती है परंतु निरीह जनता मूक होकर उस भ्रष्ट नेता को टुकुर टुकुर देखती रहती है और फिर से उसी को वोट देकर जिता देती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि एमएलए और एमपी के वोटो की गिनती बूथवार होती है, और वोटो की गिनती करने से पूर्व उनकी मिक्सिंग नहीं की जाती है। इसी कारण वह बाहुबली, भ्रष्ट और पैसे वाला नेता इस बात को जान जाता है कि किस बूथ पर कितने लोगों ने उसकी खिलाफत की है। भारत के चुनावी सिस्टम में बहुत बड़े दर्जे का फर्जीवाड़ा भी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। आम जनता अपनी रोजी-रोटी की भाग दौड़ में इन सब चीजों को बारीकी से देख नहीं पा रही है या बुरी तरीके से डर गई है परंतु इस सड़े हुए सिस्टम का प्रभाव साधारण जनता पर अब बुरी तरीके से पड़ने लग गया है।

यही कारण है कि जनता का उसके शासको पर से तेजी से विश्वास समाप्त हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी एक दूसरे की चोरी बेईमानी की बहुत बारीकी से जानकारी रहती है परंतु क्योंकि उनमें से भी कई अधिकारी पाक साफ नहीं होते हैं इसलिए वह भी गूंगे बने रहते हैं। ऐसे अधिकारी जिस दिन सेवा निवृत होते हैं उस दिन तक तो पूरे तरीके से डरे सहमे होकर नैतिक साहस की कमी के साथ बाकी का जीवन जी करके इस संसार से विदा हो रहे हैं।

इस प्रकार हमारे चारों ओर अब जिस प्रकार का समाज बन गया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्थिति अत्यंत गंभीर है एवं बहुत बड़ी सर्जरी मांग रही है। दूसरी ओर भ्रष्ट लोग भी धीरे-धीरे इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि साधारण व्यक्ति उनसे किसी प्रकार का विरोध लेने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। दिखाने को प्रतिवर्ष अधिकारी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिटर्न भी भरते हैं परंतु उसमें ना तो भूमि की वास्तविक एवं सटीक लोकेशन एवं क्षेत्रफल ही प्राय अंकित किया जाता है और ना ही उसकी वास्तविक बाजार कीमत ही अंकित की जाती है। यह कैसा देश है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त लगभग आधी रकम में ही सरकारी रिकॉर्ड में दिखाई जाती है और शेष आधी कीमत पूर्णतया ब्लैक मनी के रूप में दी जाती है। विचार करना चाहिए कि किस प्रकार की नोटबंदी हमने की थी और किस प्रकार का लेनदेन हम हमारे सार्वजनिक जीवन में करते हैं । यह पतन ऊपर से शुरू हो गया है और नी